National Court of Appeal

The Chief Justice of India N.V. Ramana has urged the Government to seriously consider Attorney General K.K.Venugopal's suggestion to restructure the judiciary to include **four National Courts of Appeals.**

- He remarked that the judicial structure has remained stagnant since Independence and with four appellate courts, pendency will be remarkably reduced.

About the National Court of Appeal:

The National Court Appeal with regional benches in Chennai, Mumbai and Kolkata is meant to act as final court of justice in dealing with appeals from the decisions of the High Courts and tribunals within their region in civil, criminal, labour and revenue matters.

- In such a scenario, a much-relieved Supreme Court of India situated in Delhi would only hear matters of constitutional law and public law.

राष्ट्रीय अपील न्यायालय

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने सरकार से अपील की चार राष्ट्रीय न्यायालयों को शामिल करने के लिए न्यायपालिका के पुनर्गठन के लिए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के सुझाव पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है।

• उन्होंने टिप्पणी की कि स्वतंत्रता के बाद से न्यायिक संरचना स्थिर रही है और चार अपीलीय अदालतों के साथ, लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी आएगी।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय के बारे में:

चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में क्षेत्रीय पीठों के साथ राष्ट्रीय न्यायालय अपील का उद्देश्य दीवानी, आपराधिक, श्रम और राजस्व मामलों में अपने क्षेत्र के भीतर उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों की अपीलों से निपटने में न्याय के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करना है।

• ऐसे परिदृश्य में, दिल्ली में स्थित भारत का सर्वोच्च न्यायालय केवल संवैधानिक कानून और सार्वजनिक कानून के मामलों की सुनवाई करेगा।

NASA's Perseverance rover

NASA's Perseverance Mars Rover has made a video of the 13th flight of the **Ingenuity Mars Helicopter** sent by the agency.

About Perseverance Rover:

It was launched in 2020 aboard a United Launch Alliance Atlas V.

Why is this mission significant?

1. It carried a unique instrument, **MOXIE or Mars Oxygen ISRU Experiment:** which for the first time manufactured molecular oxygen on Mars using carbon dioxide from the carbon-dioxide-rich atmosphere (ISRU means In Situ Resource Utilization: or the use of local resources to meet human needs or requirements of the spacecraft).
2. It carried **Ingenuity,** the first ever helicopter to fly on Mars.
3. It is **the planned first step to bring back rock samples from Mars** for analysis in sophisticated laboratories on Earth: with the goal of looking for biosignatures: or signatures of present or past life.

These are some of the key mission objectives:

1. Look for signs of ancient microbial life.
2. Collect Martian rock and dust samples for later return to Earth.

3. Deliver an experimental helicopter.
4. Study the climate and geology of Mars.
5. Demonstrate technology for future Mars missions.

What is the reason for the near-term interest in Mars?

1. Mars is located in the very near backyard (about 200 million km away).
2. It is a planet that humans can aspire to visit or to stay for a longer duration.
3. Mars had flowing water and an atmosphere in the distant past: and perhaps conditions to support life.
4. It also has implications for commercial travel.

नासा का पर्सवेरेंस रोवर

नासा के पर्सवेरेंस मार्स रोवर ने एजेंसी द्वारा भेजे गए इनजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर की 13वीं उड़ान का वीडियो बनाया है।

दृढ़ता रोवर के बारे में:

इसे 2020 में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी में लॉन्च किया गया था।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मिशन?

1. इसने एक अनूठा उपकरण, मोक्सी या मार्स ऑक्सीजन ISRU प्रयोग किया: जिसने पहली बार कार्बन-डाइऑक्साइड-समृद्ध वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके मंगल पर आणविक ऑक्सीजन का निर्माण किया (ISRU का अर्थ है स्वस्थानी संसाधन उपयोग में: या स्थानीय संसाधनों

का उपयोग) मानव की जरूरतों या अंतरिक्ष यान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए)।

2. इसने मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर इनजेनिटी ले जाया।

3. यह पृथ्वी पर परिष्कृत प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए मंगल ग्रह से चट्टान के नमूनों को वापस लाने के लिए नियोजित पहला कदम है: बायोसिग्नेचर की तलाश के लक्ष्य के साथ: या वर्तमान या पिछले जीवन के हस्ताक्षर।

ये कुछ प्रमुख मिशन उद्देश्य हैं:

1. प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेतों की तलाश करें।

2. बाद में पृथ्वी पर लौटने के लिए मंगल ग्रह की चट्टान और धूल के नमूने एकत्र करें।

3. एक प्रयोगात्मक हेलीकाप्टर वितरित करें।

4. मंगल ग्रह की जलवायु और भूविज्ञान का अध्ययन करें।

5. भविष्य के मंगल मिशनों के लिए प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन।

मंगल ग्रह में निकट भविष्य की रुचि का कारण क्या है?

1. मंगल बहुत निकट पिछवाड़े (लगभग 200 मिलियन किमी दूर) में स्थित है।

2. यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जाने या अधिक समय तक रहने की इच्छा मनुष्य कर सकता है।
3. मंगल के पास बहता पानी और सुदूर अतीत में एक वातावरण था: और शायद जीवन का समर्थन करने के लिए स्थितियां।
4. इसका व्यावसायिक यात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है।

InFinity Forum

Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate **InFinity Forum**, a thought leadership Forum on **FinTech**, on **3rd December, 2021**.

The event is being hosted by International Financial Services Centres Authority (IFSCA), under the aegis of Government of India in collaboration with GIFT City and Bloomberg on December 3 and 4, 2021. Indonesia, South Africa and the U.K. are partner countries in the first edition of the Forum.

InFinity Forum will bring together the leading minds of the world in policy, business, and technology to discuss and come up with actionable insight into how technology and innovation can be leveraged by the FinTech industry for inclusive growth and serving humanity at large.

The agenda of the **Forum will focus on the theme of 'Beyond'**; with **various sub themes including FinTech beyond boundaries**, with governments and businesses focussing beyond the geographical boundaries in the development of global stack to promote financial inclusiveness; FinTech beyond Finance, by having convergence with emerging areas such as **SpaceTech, GreenTech and AgriTech** to drive sustainable development; and FinTech Beyond Next, with focus on how Quantum Computing could impact the nature of Fintech industry in the future and promote new opportunities.

The forum will witness participation from over 70 countries. Key speakers at the Forum includes Finance Minister of Malaysia Tengku Mr. Zafrul Aziz, Finance Minister of Indonesia Ms Sri Mulyani Indrawati, Minister of Creative Economy Indonesia Mr. Sandiaga S Uno, Chairman and MD, Reliance Industries Mr. Mukesh Ambani, Chairman & CEO SoftBank Group Corp. Mr. Masayoshi Son, Chairman and CEO, IBM Corporation Mr. Arvind Krishna, MD and CEO Kotak Mahindra Bank Limited Mr. Uday Kotak, among others. NITI Aayog, Invest India, FICCI and NASSCOM are some of the key partners to this year's Forum.

About IFSCA

The **International Financial Services Centres Authority (IFSCA), headquartered at GIFT City, Gandhinagar Gujarat**, has been established under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019. It works as a unified authority for the development and regulation of financial products, financial services and financial institutions in the International Financial Services Centre (IFSC) in India. At present, the GIFT IFSC is the maiden international financial services centre in India.

इन्फिनिटी फोरम

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर, 2021 को फिनटेक पर एक विचारशील नेतृत्व फोरम, इनफिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे।

यह आयोजन 3 और 4 दिसंबर, 2021 को गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूके पहले भागीदार देश हैं। मंच का संस्करण।

इनफिनिटी फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी दिमागों को एक साथ लाएगा और चर्चा करेगा कि कैसे समावेशी विकास और बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा के लिए फिनटेक उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाया जा सकता है।

फोरम का एजेंडा 'बियॉन्ड' की थीम पर केंद्रित होगा; वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्टैक के विकास में भौगोलिक सीमाओं से परे सरकारों और व्यवसायों

के साथ सीमाओं से परे फिनटेक सहित विभिन्न उप विषयों के साथ; वित्त से परे फिनटेक, सतत विकास को चलाने के लिए स्पेसटेक, ग्रीनटेक और एग्रीटेक जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ अभिसरण करके; और फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट, इस पर ध्यान देने के साथ कि क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य में फिनटेक उद्योग की प्रकृति को कैसे प्रभावित कर सकती है और नए अवसरों को बढ़ावा दे सकती है।

फोरम में 70 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। फोरम में मुख्य वक्ताओं में मलेशिया के वित्त मंत्री टेंगकू श्री जफरुल अजीज, इंडोनेशिया के वित्त मंत्री सुश्री मुलयानी इंद्रावती, रचनात्मक अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया के मंत्री श्री सैंडियागा एस ऊनो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और एमडी श्री मुकेश अंबानी, अध्यक्ष और सीईओ शामिल हैं। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प श्री मासायोशी सोन, अध्यक्ष और सीईओ, आईबीएम कॉर्पोरेशन श्री अरविंद कृष्णा, एमडी और सीईओ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड श्री उदय कोटक, अन्य। नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया, फिक्की और नैसकॉम इस साल के फोरम के कुछ प्रमुख भागीदार हैं।

IFSCA के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA), जिसका मुख्यालय GIFT सिटी, गांधीनगर गुजरात में है, को

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया है। यह वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में काम करता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में वित्तीय संस्थान। वर्तमान में, GIFT IFSC भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।

Index of Eight Core Industries

The Office of Economic Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) is releasing Index of Eight Core Industries (ICI) for the Month of October, 2021.ICI measures combined and individual performance of production in selected eight core industries viz. Coal, Crude Oil, Natural Gas, Refinery Products, Fertilizers, Steel, Cement and Electricity.The Eight Core Industries comprise 40.27 percent of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). Details of yearly and monthly indices and growth rates are provided at Annex I & II respectively.

The combined Index of Eight Core Industries stood at 136.2 in October 2021, which increased by7.5 per cent (provisional) as compared to the Index ofOctober 2020. The production of Coal, Natural Gas, Refinery Products, Fertilizers,Steel, Cement and Electricity industries increased in October 2021 over the corresponding periodof last year.

Final growth rate of Index of Eight Core Industries for July 2021 is revised to 9.9%from its provisional level 9.4%. The growth rate of ICI during April-October2021-22 was 15.1% (P) as compared to the corresponding period of lastFY.

The summary of the Index of Eight Core Industries is given below:

Coal –Coal production (weight: 10.33 per cent) increased by 14.6 percent in October,2021 overOctober,2020. Its cumulative index increased by 12.2 per cent during April to October,2021-22 over corresponding period of the previous year.

Crude Oil–Crude Oil production (weight: 8.98 per cent) declined by 2.2 percent in October,

2021 over October,2020. Its cumulative index declined by 2.8 percent during April to October, 2021-22over the corresponding period of previous year.

Natural Gas - Natural Gas production (weight: 6.88 per cent) increased by 25.8 per cent in October, 2021over October, 2020. Its cumulative index increased by 22.6 per cent during April to October, 2021-22 over the corresponding period of previous year.

Petroleum Refinery Products–Petroleum Refinery production (weight: 28.04 per cent) increased by 14.4 per cent in October, 2021 over October, 2020. Its cumulative index increased by 11.7 per cent during April to October, 2021-22over the corresponding period of previous year.

Fertilizers – Fertilizers production (weight: 2.63 per cent) increased by0.04 percent in October, 2021 over October, 2020. Its cumulative index decreased by 1.1 per cent during April to October, 2021-22 over the corresponding period of previous year.

Steel –Steel production (weight: 17.92 per cent) increased by 0.9 per cent in October, 2021 over October, 2020. Its cumulative index increased by 28.6 percent during April to October, 2021-22 over the corresponding period of previous year.

Cement –Cement production (weight: 5.37 per cent) increased by 14.5 percent in October, 2021 over October, 2020. Its cumulative index increased by 33.6 per cent during April to October, 2021-22 over the corresponding period of previous year.

Electricity –Electricity generation (weight: 19.85 per cent) increased by 2.8percent in October, 2021 over October,2020. Its cumulative index increased by 11.3 per cent during April to October, 2021-22 over the corresponding period of previous year.

आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक

आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) अक्टूबर, 2021 के महीने के लिए आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) का सूचकांक जारी कर रहा है। ICI चयनित आठ प्रमुख उद्योगों में उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली। आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन

सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है। वार्षिक और मासिक सूचकांकों और विकास दर का विवरण क्रमशः अनुबंध I और II में दिया गया है।

आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अक्टूबर 2021 में 136.2 रहा, जो अक्टूबर 2020 के सूचकांक की तुलना में 7.5 प्रतिशत (अनंतिम) बढ़ा। कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अक्टूबर 2021 में उद्योगों में वृद्धि हुई।

जुलाई 2021 के लिए आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को इसके अनंतिम स्तर 9.4% से संशोधित कर 9.9% कर दिया गया है। अप्रैल-अक्टूबर 2021-22 के दौरान आईसीआई की वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.1% (पी) थी।

आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का सारांश नीचे दिया गया है:

कोयला-कोयला उत्पादन (भारांक: 10.33 प्रतिशत)

अक्टूबर, 2021 में अक्टूबर, 2020 की तुलना में 14.6 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल से अक्टूबर 2021-22 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.2 प्रतिशत बढ़ा।

कच्चा तेल-कच्चे तेल का उत्पादन (भारांक: 8.98 प्रतिशत) अक्टूबर, 2021 में अक्टूबर, 2020 की तुलना में 2.2 प्रतिशत कम हो गया। अप्रैल से अक्टूबर, 2021-22 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.8 प्रतिशत कम हो गया।

प्राकृतिक गैस - प्राकृतिक गैस उत्पादन (भारांक: 6.88 प्रतिशत) अक्टूबर, 2021 में अक्टूबर, 2020 की तुलना में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से अक्टूबर, 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22.6 प्रतिशत बढ़ा।
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद-पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (भारांक: 28.04 प्रतिशत) अक्टूबर, 2021 में अक्टूबर, 2020 की तुलना में 14.4 प्रतिशत बढ़ा। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से अक्टूबर, 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.7 प्रतिशत बढ़ा है। .
उर्वरक-उर्वरक उत्पादन (भारांक: 2.63 प्रतिशत) अक्टूबर, 2021 में अक्टूबर, 2020 की तुलना में 0.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से अक्टूबर, 2021-

22 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.1 प्रतिशत कम हुआ।

स्टील-इस्पात उत्पादन (भारांक: 17.92 प्रतिशत) अक्टूबर, 2021 में अक्टूबर, 2020 की तुलना में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से अक्टूबर, 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 28.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सीमेंट-सीमेंट उत्पादन (भारांक: 5.37 प्रतिशत) अक्टूबर, 2021 में अक्टूबर, 2020 की तुलना में 14.5 प्रतिशत बढ़ा। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से अक्टूबर, 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 33.6 प्रतिशत अधिक है।

बिजली-बिजली उत्पादन (भार: 19.85 प्रतिशत) अक्टूबर, 2021 में अक्टूबर, 2020 की तुलना में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल से अक्टूबर, 2021-22 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.3 प्रतिशत बढ़ा।

Wanchuwa festival

- Wanchuwa festival is celebrated by Tiwa tribesmen to mark their good harvest.

- It comes with songs, dances, a bunch of rituals and people clad in their native attires.
- The people of Tiwa tribe associate the bountiful harvest with the higher power from nature. This takes the form of pigs' skulls and bones which act as deities and are preserved through many generations.
- Tiwa also known as Lalung is indigenous community inhabiting the states of Assam and Meghalaya and are also found in some parts of Arunachal Pradesh and Manipur.

वांचुवा उत्सव

• वांचुवा त्योहार तिवा आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है।

• यह गाने, नृत्य, अनुष्ठानों के एक समूह के साथ आता है और लोग अपने मूल परिधान में आते हैं।

• तिवा जनजाति के लोग भरपूर फसल को प्रकृति की उच्च शक्ति से जोड़ते हैं। यह सूअरों की खोपड़ी और हड्डियों का रूप लेता है जो देवताओं के रूप में कार्य करते हैं और कई पीढ़ियों तक संरक्षित रहते हैं।

• तिवा, जिसे लालुंग के नाम से भी जाना जाता है, असम और मेघालय राज्यों में रहने वाला एक स्वदेशी समुदाय है और यह अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है।

Veer Savarkar

Central Information Commissioner (CIC) Uday Mahurkar recently said the era of V D Savarkar, known as the architect of Hindutva ideology, has already set in in India and that his personality is above Bharat Ratna, the highest civilian honour.

What's the issue?

A quote attributed to Savarkar has been going around in academic circles which shows that Savarkar supported **Jinnah's two nation theory.**

- However experts are of the opinion that while Jinnah wanted partition, Savarkar wanted Territorial Integrity of India.
- Jinnah wanted minority representation while Savarkar wanted Majority rule.
- Jinnah wanted residuary powers to reside in the provinces but Savarkar wanted them to reside in Centre.
- Jinnah wanted reservation in recruitment to civil/public service while Savarkar wanted merit to be the sole criterion.

Who is Veer Savarkar?

Born on May 28, 1883 in Bhagur, a city in Maharashtra's Nashik.

Nationalism and social reforms:

- Formed a youth organization- **Mitra Mela,** this organization was put into place to bring in national and revolutionary ideas.
- He was against foreign goods and propagated the idea of Swadeshi.
- He championed **atheism and rationality** and also disapproved orthodox Hindu belief. In fact, he even dismissed cow worship as superstitious.
- He also Worked on **abolishment of untouchability** in Ratnagiri. Dr Babasaheb Ambedkar also compared his work to **Lord Buddha.**
- Vinayak Savarkar was a president of **Hindu Mahasabha** from 1937 to 1943.
- When congress ministries offered resignation on 22nd oct 1939, Hindu mahaasabha under his leadership cooperated with Muslim league to form government in provinces like Sindh, Bengal and NWFP.
- In Pune, Savarkar founded **the "Abhinav Bharat Society".**
- He joined Tilak's **Swaraj Party.**
- He founded **the Free India Society.** The Society celebrated important dates on the Indian calendar including festivals, freedom movement landmarks, and was dedicated to furthering discussion about Indian freedom.
- He believed and advocated the use of arms to free India from the British and created a network of Indians in England, equipped with weapons.

Important works:

1. Book- The History of the war of Indian Independence.
2. An armed revolt against the Morley-Minto reform.
3. Two-nation theory in his book 'Hindutva'.

वीर सावरकर

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) उदय माहूरकर ने हाल ही में कहा था कि हिंदुत्व विचारधारा के निर्माता के रूप में जाने जाने वाले वी डी सावरकर का युग पहले ही भारत में आ चुका है और उनका व्यक्तित्व सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से ऊपर है।

मुद्दा क्या है?

सावरकर का एक उद्धरण अकादमिक हलकों में घूम रहा है जो दर्शाता है कि सावरकर ने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था।

• हालांकि विशेषज्ञों की राय है कि जहां जिन्ना विभाजन चाहते थे, सावरकर भारत की क्षेत्रीय अखंडता चाहते थे।

• जिन्ना अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व चाहते थे जबकि सावरकर बहुमत शासन चाहते थे।

• जिन्ना चाहते थे कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में रहें लेकिन सावरकर चाहते थे कि वे केंद्र में रहें।

• जिन्ना सिविल/सार्वजनिक सेवा में भर्ती में आरक्षण चाहते थे जबकि सावरकर चाहते थे कि योग्यता ही एकमात्र मानदंड हो।

वीर सावरकर कौन हैं?

28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के एक शहर भागूर में जन्म।

राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार:

• एक युवा संगठन - मित्र मेला का गठन, इस संगठन को राष्ट्रीय और क्रांतिकारी विचारों को लाने के लिए स्थापित किया गया था।

• वह विदेशी वस्तुओं के खिलाफ थे और उन्होंने स्वदेशी के विचार का प्रचार किया।
• उन्होंने नास्तिकता और तर्कसंगतता का समर्थन किया और रूढ़िवादी हिंदू विश्वास को भी अस्वीकार कर दिया। वास्तव में, उन्होंने गो-पूजा को भी अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया।
• उन्होंने रत्नागिरी में अस्पृश्यता उन्मूलन पर भी काम किया। डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर ने भी अपने काम की तुलना भगवान बुद्ध से की।
• विनायक सावरकर 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे।
• जब 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफे की पेशकश की, तो उनके नेतृत्व में हिंदू महासभा ने सिंध, बंगाल और एनडब्ल्यूएफपी जैसे प्रांतों में सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग के साथ सहयोग किया।
• पुणे में सावरकर ने "अभिनव भारत सोसाइटी" की स्थापना की।
• वे तिलक की स्वराज पार्टी में शामिल हो गए।
• उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी ने भारतीय कैलेंडर पर त्योहारों, स्वतंत्रता आंदोलन स्थलों सहित

महत्वपूर्ण तिथियों का जश्न मनाया, और भारतीय स्वतंत्रता के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित था।

• उन्होंने विश्वास किया और भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए हथियारों के इस्तेमाल की वकालत की और हथियारों से लैस इंग्लैंड में भारतीयों का एक नेटवर्क बनाया।

महत्वपूर्ण कार्य:

1. पुस्तक- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास।
2. मॉर्ले-मिंटो सुधार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह।
3. द्वि-राष्ट्र सिद्धांत ने अपनी पुस्तक 'हिंदुत्व' में।

J&K's Roshni Act

A year after the High Court struck down the Roshni Act, the Jammu and Kashmir government has now begun an exercise to retrieve the land granted under this Act to beneficiaries.

Background:

There are allegations related to irregularities in the implementation of **the Jammu and Kashmir States Land (vesting of ownership to the occupants) Act,** also known as **Roshini Act,** which has now been declared null and void.

- On November 1, 2020, the Union Territory administration cancelled all land transfers that took place under the JK State Land (Vesting of Ownership to the Occupants) Act, 2001.

About the Roshini Act:

Enacted in 2001, the law sought to regularise unauthorised land.

The Act envisaged **the transfer of ownership rights of state land** to its occupants, subject to the payment of a cost, as determined by the government.

- The government said **the revenue generated would be spent on commissioning hydroelectric power projects,** hence the name **"Roshni".**
- Further, through amendments, the government also gave **ownership rights of agricultural land to farmers occupying it for free,** charging them only Rs 100 per kanal as documentation fee.

Why it was scrapped?

- In 2009, the State Vigilance Organisation registered an FIR against several government officials for alleged criminal conspiracy to illegally possess and vest ownership of state land to occupants who did not satisfy criteria under the Roshni Act.
- In 2014, a report by the Comptroller and Auditor General (CAG) estimated that against the targeted Rs 25,000 crore, only Rs 76 crore had been realised from the transfer of encroached land between 2007 and 2013, thus defeating the purpose of the legislation.
- The report blamed irregularities including arbitrary reduction in prices fixed by a standing committee, and said this was done to benefit politicians and affluent people.

जम्मू–कश्मीर का रोशनी अधिनियम

उच्च न्यायालय द्वारा रोशनी अधिनियम को रद्द करने के एक साल बाद, जम्मू और कश्मीर सरकार ने अब लाभार्थियों को इस अधिनियम के तहत दी गई भूमि को पुनः प्राप्त करने की कवायद शुरू कर दी है।

पृष्ठभूमि:

जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि (अधिभोगियों को स्वामित्व का अधिकार) अधिनियम, जिसे रोशनी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित

आरोप हैं, जिसे अब शून्य और शून्य घोषित कर दिया गया है।

• 1 नवंबर, 2020 को, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जेके राज्य भूमि (अधिभोगियों के स्वामित्व का अधिकार) अधिनियम, 2001 के तहत होने वाले सभी भूमि हस्तांतरण को रद्द कर दिया।

रोशिनी अधिनियम के बारे में:

2001 में अधिनियमित, कानून ने अनधिकृत भूमि को नियमित करने की मांग की।

इस अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान के अधीन, राज्य की भूमि के स्वामित्व अधिकारों को अपने कब्जेदारों को हस्तांतरित करने की परिकल्पना की गई थी।

• सरकार ने कहा कि उत्पन्न राजस्व पनबिजली परियोजनाओं को चालू करने पर खर्च किया जाएगा, इसलिए इसका नाम "रोशनी" है।

• इसके अलावा, संशोधनों के माध्यम से, सरकार ने कृषि भूमि पर कब्जा करने वाले किसानों को मुफ्त में स्वामित्व अधिकार भी दिया, उनसे दस्तावेज शुल्क के रूप में केवल 100 रुपये प्रति कनाल चार्ज किया।

इसे क्यों खंगाला गया?

• 2009 में, राज्य सतर्कता संगठन ने कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध रूप से कब्जा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश के लिए प्राथमिकी दर्ज की और रोशनी अधिनियम के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले लोगों को राज्य की भूमि का स्वामित्व सौंप दिया।

• 2014 में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि लक्षित 25,000 करोड़ रुपये के मुकाबले, 2007 और 2013 के बीच अतिक्रमित भूमि के हस्तांतरण से केवल 76 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी, इस प्रकार कानून के उद्देश्य को विफल कर दिया।

• रिपोर्ट में एक स्थायी समिति द्वारा तय की गई कीमतों में मनमानी कमी सहित अनियमितताओं को दोषी ठहराया गया और कहा गया कि यह राजनेताओं और संपन्न लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था।

“Story of World’s Largest Democracy’s Election”

The Election Commission of India in association with the High Commission of India, Pretoria; Consulate General of India, Johannesburg and Electoral Commission of South Africa, participated in an international virtual seminar on **“Story of World’s Largest Democracy’s Election” in India** on

30th November 2021. The Webinar was attended by over 50 participants from the Indian diaspora, academicians and students from different universities in South Africa.

In his keynote Address, **Shri Sushil Chandra, Chief Election Commissioner of India** stated that conducting elections in India is a mammoth task with over 937 million registered electors in the country by now. He added that ECI sets up polling booths within walking distance of every village, hamlet and habitation with the aim of 'No Voter to be Left Behind'. While sharing the experience of conducting elections in six states amidst the COVID pandemic, Shri Chandra mentioned several initiatives adapted to ensure smooth conduct of elections despite challenges posed. He highlighted steps like curtailing the maximum number of voters at a polling station from 1500 to 1000 and extending polling hours by an hour in order to decongest polling spaces; postal ballot facility for 80+ senior citizens, PwDs and COVID affected individuals where ECI literally brought the polling station to their doorstep. Shri Sushil Chandra also gave an insight into the participation of women in Indian elections, which has seen remarkable increase over the years.

ECI **is presently the Chair of Association of World Election Bodies where EC of South Africa is the Vice Chair of AWEB.** The Election Commission of India and Electoral Commission of South Africa enjoy warm and friendly relations. Both the institutions signed a Memorandum of Understanding in October 2011 for mutual cooperation in the field of Electoral Management and Administration. Under this framework, both the EMBs have exchanged good practices from time to time in different fields of Electoral Management.

A short film titled **'Making of Indian Constitution'** to commemorate the Constitution Day was also screened during the webinar.

"दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव की कहानी"
भारत के उच्चायोग, प्रिटोरिया के सहयोग से भारत का चुनाव आयोग; भारत के महावाणिज्य दूतावास, जोहान्सबर्ग और दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग ने 30 नवंबर 2021 को भारत में "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव की

कहानी" पर एक अंतरराष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी में भाग लिया। वेबिनार में भारतीय प्रवासी, शिक्षाविदों और 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र।

अपने मुख्य भाषण में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री सुशील चंद्रा ने कहा कि भारत में चुनाव कराना अब तक देश में 937 मिलियन से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के साथ एक विशाल कार्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 'कोई मतदाता पीछे न छूटे' के उद्देश्य से हर गांव, बस्ती और बस्ती से पैदल दूरी के भीतर मतदान केंद्र स्थापित करता है। COVID महामारी के बीच छह राज्यों में चुनाव कराने के अनुभव को साझा करते हुए, श्री चंद्रा ने चुनौतियों के बावजूद चुनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई कई पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1500 से घटाकर 1000 करने और मतदान स्थलों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए मतदान के घंटे को एक घंटे तक बढ़ाने जैसे कदमों पर प्रकाश डाला; 80+ वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और COVID प्रभावित व्यक्तियों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा, जहां ECI सचमुच मतदान केंद्र को उनके दरवाजे तक ले आया। श्री सुशील चंद्रा ने भारतीय चुनावों में

महिलाओं की भागीदारी के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
ECI वर्तमान में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का अध्यक्ष है, जहां दक्षिण अफ्रीका का EC AWEB का उपाध्यक्ष है। भारत के चुनाव आयोग और दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों संस्थानों ने चुनावी प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए अक्टूबर 2011 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस ढांचे के तहत, दोनों ईएमबी ने समय-समय पर चुनावी प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी प्रथाओं का आदान-प्रदान किया है।
वेबिनार के दौरान संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 'भारतीय संविधान का निर्माण' नामक एक लघु फिल्म भी दिखाई गई।

Representation of Women in Panchayat System

Article 243D of the Constitution of India provides for not less than one-third reservation for women out of total number of seats to be filled by direct election and number of offices of chairpersons of Panchayats. However, as per the information available with the Ministry, 21 States namely, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand and West Bengal, have made provision of 50% reservation for women in Panchayati Raj Institutions in their respective State Panchayati Raj Acts. In respect of remaining States, Constitutional provision as prescribed in Article 243D applies.

‘Panchayat’, being ‘Local Government’, is a State subject and part of Seventh Schedule of the Constitution. Accordingly, all Panchayat related matters, including representation of women in Panchayat systems, are governed by the respective State Panchayati Raj Acts and rules, subject to the provisions of the Constitution. However, Government has been encouraging increased involvement of women in the functioning of Panchayats through active participation in the Gram Sabha meetings for preparation of Gram Panchayat Development Plans and various schemes being implemented by the Panchayats. This Ministry has also issued advisories to the States to facilitate holding of separate Ward Sabha and MahilaSabha meetings prior to Gram Sabha meetings, enhancing the presence and participation of women in Gram Sabha and Panchayat meetings, allocation of Panchayat funds for women centric activities, combating the evil of women trafficking, female foeticide, child marriage etc.

Article 280 (3) (bb) of the Constitution of India provides for the Finance Commission to make recommendations regarding the measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats in the State on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the State. Accordingly, to improve the functioning of Panchayati Raj Institutions, including women related activities; funds have been recommended by Central Finance Commissions successively.

पंचायत व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243डी में पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या और प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि, मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 21 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती

राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। शेष राज्यों के संबंध में, अनुच्छेद 243डी में निर्धारित संवैधानिक प्रावधान लागू होते हैं।

'पंचायत', 'स्थानीय सरकार' होने के कारण, राज्य का विषय है और संविधान की सातवीं अनुसूची का हिस्सा है। तदनुसार, पंचायत प्रणाली में महिलाओं के प्रतिनिधित्व सहित पंचायत से संबंधित सभी मामले संविधान के प्रावधानों के अधीन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित होते हैं। तथापि, सरकार ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की तैयारी के लिए ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। इस मंत्रालय ने राज्यों को ग्राम सभा की बैठकों से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने, ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने, महिला केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि का आवंटन, महिला तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि की बुराई।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 (3) (बी बी) वित्त आयोग को राज्य में पंचायतों के संसाधनों को पूरक करने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए प्रदान करता है। राज्य के वित्त आयोग द्वारा तदनुसार, महिला संबंधित गतिविधियों सहित पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में सुधार करना; केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा क्रमिक रूप से निधियों की सिफारिश की गई है।

Barbados becomes the World's newest republic

Barbados has become the **World's newest republic,** around 400 years after it became a British colony. Barbados is said to have been made a **'slave society** by the **British.** It first became an English colony in **1625.** It gained its independence in **1966.** Barbados, the Caribbean Island nation, removed Queen Elizabeth II as the head of the state.

Dame Sandra Prunella Mason took over as the President of Barbados. He was selected to become the first president of Barbados in October 2021. He was selected as President of Barbados, at a joint meeting of both the Houses of Parliament of Barbados. His name was announced by Speaker of the House of Assembly, Arthur Holder.

- Barbados Capital: Bridgetown;
- Barbados Currency: Barbados Dollar.

बारबाडोस बना दुनिया का सबसे नया गणतंत्र

ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। कहा जाता है कि बारबाडोस को अंग्रेजों ने 'गुलाम समाज' बना दिया था।

यह पहली बार 1625 में एक अंग्रेजी उपनिवेश बन गया। इसने 1966 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। कैरेबियन द्वीप राष्ट्र बारबाडोस ने राज्य के प्रमुख के रूप में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हटा दिया।

डेम सैंड्रा प्रुनेला मेसन ने बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें अक्टूबर 2021 में बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति बनने के लिए चुना गया था। बारबाडोस की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उन्हें बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उनके नाम की घोषणा हाउस ऑफ असेंबली के स्पीकर आर्थर होल्डर ने की।

- बारबाडोस राजधानी: ब्रिजटाउन;
- बारबाडोस मुद्रा: बारबाडोस डॉलर।

Varanasi became 1st Indian city to start Ropeway Service

Varanasi, a city in **Uttar Pradesh** is all set to become the first Indian city to start ropeway service as a mode of public transport in order to ease the traffic congestion. The proposed ropeway will be constructed between **Cantt Railway Station (Varanasi Junction)** to **Church Square (Godauliya)** covering an aerial distance of **3.45 km.** Its outlay is over Rs 400 crore which is divided between Central Government and State Government at 80:20. India will be the third country in the world after Bolivia and Mexico to use a ropeway for public transport.

वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया

वाराणसी, उत्तर प्रदेश का एक शहर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने के लिए तैयार है। प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कैंट रेलवे स्टेशन (वाराणसी जंक्शन) से चर्च स्क्वायर (गोदौलिया) के बीच 3.45 किमी की हवाई दूरी को कवर करते हुए किया जाएगा। इसका परिव्यय 400 करोड़ रुपये से अधिक है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 80:20 पर विभाजित है। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश होगा।

Lionel Messi Wins A Seventh Ballon d'Or

Lionel Messi has won the **Ballon d'Or** for a seventh time after being named as the **best player** in **2021 by France Football.** Messi scored 41 goals and registered 17 assists in 56 appearances in all competitions for club and country and led Argentina to a long-awaited Copa America win in the summer. **Messi** also won in **2009, 2010, 2011, 2012, and in 2015**. The 34-year-old scored 38 goals in 48 games last season for Barcelona and won the Copa del Rey before captaining Argentina to Copa America glory in July.

Ballon d'Or 2021 Winners:

- Ballon d'Or (Men): **Lionel Messi (PSG/Argentina)**
- Club of the year: **Chelsea Football Club**
- Yashin Trophy for best goalkeeper: **Gianluigi Donnarumma (PSG/Italy)**
- Ballon d'Or (Women): **Alexia Putellas (Barcelona/Spain)**
- Striker of the year: **Robert Lewandowski (Bayern Munich/Poland)**
- Kopa Trophy for best young male player: **Pedri (Barcelona/Spain)**

लियोनेल मेस्सी ने जीता सातवां बैलन डी'ओर

फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद लियोनेल मेसी ने सातवीं बार बैलोन डी'ओर जीता है। मेस्सी ने 41 गोल किए और क्लब और देश के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 56 प्रदर्शनों में 17 सहायता दर्ज की और अर्जेंटीना को गर्मियों में लंबे समय से प्रतीक्षित कोपा अमेरिका जीत तक पहुंचाया। मेस्सी ने 2009, 2010, 2011, 2012 और 2015 में भी जीत हासिल की। 34 वर्षीय ने बार्सिलोना के लिए पिछले सीजन में 48 मैचों में 38 गोल किए और जुलाई में अर्जेंटीना की कप्तानी करने से पहले कोपा डेल रे जीता।

बैलोन डी'ओर 2021 के विजेता:

• बैलन डी'ओर (पुरुष): लियोनेल मेस्सी (पीएसजी/अर्जेंटीना)

• वर्ष का क्लब: चेल्सी फुटबॉल क्लब

• सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यशिन ट्रॉफी: जियानलुइगी डोनारुम्मा (पीएसजी/इटली)

• बैलन डी'ओर (महिला): एलेक्सिया पुटेलस (बार्सिलोना/स्पेन)

• स्ट्राइकर ऑफ द ईयर: रॉबर्ट लेवांडोव्स्की (बायर्न म्यूनिख/पोलैंड)

- सर्वश्रेष्ठ युवा पुरुष खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी: पेड्रि (बार्सिलोना/स्पेन)

BSF celebrates 57th Raising Day on December 01, 2021

The **Border Security Force (BSF)** is celebrating its **57th Raising Day** on **01 December 2021.** BSF was formed on **December 1, 1965** as a unified central agency after the Indo-Pak and India-China wars for ensuring the security of the borders of India and for matters connected therewith. It is one of the five Central Armed Police Forces of the Union of India and stands as the world's largest border guarding force. BSF has been termed as the **First Line of Defence of Indian Territories.**

- **BSF Director General: Pankaj Kumar Singh;**
- **BSF Headquarters: New Delhi.**

बीएसएफ ने 01 दिसंबर, 2021 को 57वां स्थापना दिवस मनाया

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) 01 दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत-पाक और भारत-चीन युद्धों के बाद एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया था। और उससे जुड़े मामलों के लिए। यह भारत संघ के पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में खड़ा है। BSF को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा गया है।

- बीएसएफ महानिदेशक: पंकज कुमार सिंह;
- बीएसएफ मुख्यालय: नई दिल्ली।

1st ever Aharbal Festival held in J&K to promote tourism

Kulgam district administration and the Department of Tourism, **Jammu & Kashmir** organized the **1st ever Aharbal Festival at Kulgam, J & K** to promote tourism in Kashmir, particularly at the Aharbal waterfall. Aharbal falls, also known as **"Niagara Falls" of Kashmir,** is a hill station in the southwestern part of Kashmir Valley in the **Jammu and Kashmir.**

The department organized the 1st ever Lolab festival, a one-day festival at Chandigam Lolab in north Kashmir's Kupwara district, J&K, and Doodhpathri Festival, a 3-day tourism festival at Budgam, J&K, to promote Doodhpathri as an attractive tourist destination.

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू-कश्मीर में आयोजित हुआ पहला अहरबल महोत्सव
कुलगाम जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग, जम्मू और कश्मीर ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से अहरबल जलप्रपात पर, कुलगाम, जम्मू और कश्मीर में पहली बार अहरबल महोत्सव का आयोजन किया। अहरबल फॉल्स, जिसे कश्मीर के "नियाग्रा फॉल्स" के रूप में भी जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में एक हिल स्टेशन है।
विभाग ने पहली बार लोलाब उत्सव, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के चंडीगाम लोलाब, जम्मू-कश्मीर में एक

दिवसीय उत्सव और दूधपथरी को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए बडगाम, जम्मू-कश्मीर में 3 दिवसीय पर्यटन उत्सव, दूधपथरी महोत्सव का आयोजन किया।

World Aids Day 2021

Since 1988, World AIDS Day has been observed to spread awareness about this life-threatening condition caused by the human immunodeficiency virus (HIV). It is also observed to extend support to those who are fighting AIDS.

World AIDS Day is observed with a new theme every year and this year's theme **"End inequalities. End AIDS"** is aimed at WHO and its partner organisations highlighting the need for a special focus on reaching people left behind. It is calling on global leaders to rally to end inequalities that drive AIDS.

विश्व एड्स दिवस 2021
मानव इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के कारण होने वाली इस जानलेवा स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1988 से विश्व एड्स दिवस मनाया जाता रहा है। यह

उन लोगों को समर्थन देने के लिए भी मनाया जाता है जो एड्स से लड़ रहे हैं।
विश्व एड्स दिवस हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल की थीम "असमानताओं को समाप्त करें" है। एंड एड्स" का उद्देश्य डब्ल्यूएचओ और उसके सहयोगी संगठनों के लिए है जो पीछे छूटे लोगों तक पहुंचने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। यह वैश्विक नेताओं से एड्स को बढ़ावा देने वाली असमानताओं को समाप्त करने के लिए रैली करने का आह्वान कर रहा है।

Mission Indradhanush (IMI) 3.0

Two rounds of Intensified Mission Indradhanush (IMI) 3.0 of 15 days' duration were conducted recently, to reach out to the pregnant women and children who missed vaccination under routine immunisation programmes in 250 districts across 29 states/UTs.

- During **Intensified Mission Indradhanush (IMI) 3.0** around 9.5 lakh children and 2.2 lakh pregnant women were vaccinated.
- Various States and UTs have started implementation of the Intensified Mission Indradhanush 3.0.

About IMI 3.0:

It is a campaign aimed **to reach those children and pregnant women** who have been missed out or been left out of the Routine Immunisation Programme.

- **This is aimed** to accelerate the full immunisation of children and pregnant women through a mission mode intervention.
- The first phase has been rolled out from 22nd Feb. for 15 days,
- It is being **conducted in pre-identified 250 districts/urban areas across 29 States/UTs** in the country.

- **Beneficiaries from migration areas and hard to reach areas will be targeted** as they may have missed their vaccine doses during the pandemic.

Classification of districts:

As per the guidelines released for IMI 3.0**,** the districts have been classified to reflect 313 low risk; 152 medium risk; and 250 high risk districts.

What is the Mission Indradhanush?

'Mission Indradhanush' was launched by the Government of India in Decmber 2014.

- It was aimed to strengthen and re-energize the programme and achieve full immunization coverage for all children and pregnant women.
- The ultimate goal of Mission Indradhanush is to ensure full immunization with all available vaccines for children up to two years of age and pregnant women.

Intensified Mission Indradhanush (IMI) 2.0:

'Intensified Mission Indradhanush 2.0'was launched on October 31, 2019 **to ensure that not a single child in the country misses out on vaccination.**

- It had a special focus on improving coverage in areas with "low" immunisation.
- **Through 'IMI 2.0', the health ministry aims to reach** each and every child below the age of two years and all pregnant women still **uncovered/partially covered in 271 districts** of the country.

The Mission Indradhanush aims to cover all those children who are either unvaccinated, or are partially vaccinated against vaccine preventable diseases.

India's Universal Immunisation Programme (UIP) provide free vaccines against 12 life threatening diseases, to 26 million children annually. The Universal Immunization Programme provides life-saving vaccines to all children across the country free of cost to protect them against Tuberculosis, Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Polio, Hepatitis B, Pneumonia and Meningitis due to Haemophilus Influenzae type b (Hib), Measles, Rubella, Japanese Encephalitis (JE) and Rotavirus diarrhoea. (Rubella, JE and Rotavirus vaccine in select states and districts).

मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 3.0

29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 250 जिलों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों के तहत गर्भवती महिलाओं और टीकाकरण से चूकने वाले बच्चों तक पहुंचने के लिए हाल ही में 15 दिनों की अवधि के गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 3.0 के दो दौर आयोजित किए गए।

• सघन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 3.0 के दौरान लगभग 9.5 लाख बच्चों और 2.2 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।

• विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

आईएमआई 3.0 के बारे में:

यह उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुँचने के उद्देश्य से एक अभियान है जो छूट गए हैं या नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूट गए हैं।

• इसका उद्देश्य मिशन मोड हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण में तेजी लाना है।
• पहला चरण 22 फरवरी से 15 दिनों के लिए शुरू किया गया है,
• यह देश के 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से पहचाने गए 250 जिलों/शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है।
• प्रवास क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों के लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा क्योंकि वे महामारी के दौरान अपने टीके की खुराक लेने से चूक गए होंगे।
जिलों का वर्गीकरण:
आईएमआई 3.0 के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिलों को 313 कम जोखिम दर्शाने के लिए वर्गीकृत किया गया है; 152 मध्यम जोखिम; और 250 उच्च जोखिम वाले जिले।
मिशन इंद्रधनुष क्या है?
भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में 'मिशन इंद्रधनुष' की शुरुआत की गई थी।
• इसका उद्देश्य कार्यक्रम को मजबूत और फिर से सक्रिय करना और सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना था।

• मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य दो साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है।

गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 2.0:

देश में एक भी बच्चा टीकाकरण से न छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिए 31 अक्टूबर, 2019 को 'इंटेंसिफाइड मिशन इन्द्रधनुष 2.0' शुरू किया गया था।

• "कम" टीकाकरण वाले क्षेत्रों में कवरेज में सुधार पर इसका विशेष ध्यान था।

• 'आईएमआई 2.0' के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्रालय का लक्ष्य देश के 271 जिलों में दो साल से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे और सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है जो अभी भी कवर नहीं हैं/आंशिक रूप से कवर हैं।

Parker Solar Probe

The NASA probe recently made an extremely close encounter with the Sun. The probe was just 5.3 million miles away from the surface of our star and passed by at a ridiculous speed of 363,660 mph, making it **the fastest artificial object ever created.**

- Additionally, the Parker Solar Probe also broke the record for **the closest satellite to survive a near pass of the Sun.**

What next?

The probe will continue to orbit and increasingly get closer to the Sun, eventually coming within 4.3 million miles from the surface at speeds above 430,000 mph. With each pass, the probe collects valuable data about our star and relays the information

back to Earth for scientists to interpret. Information regarding solar wind, and the amount of dust particles in the area are two main sets of data the probe collects.

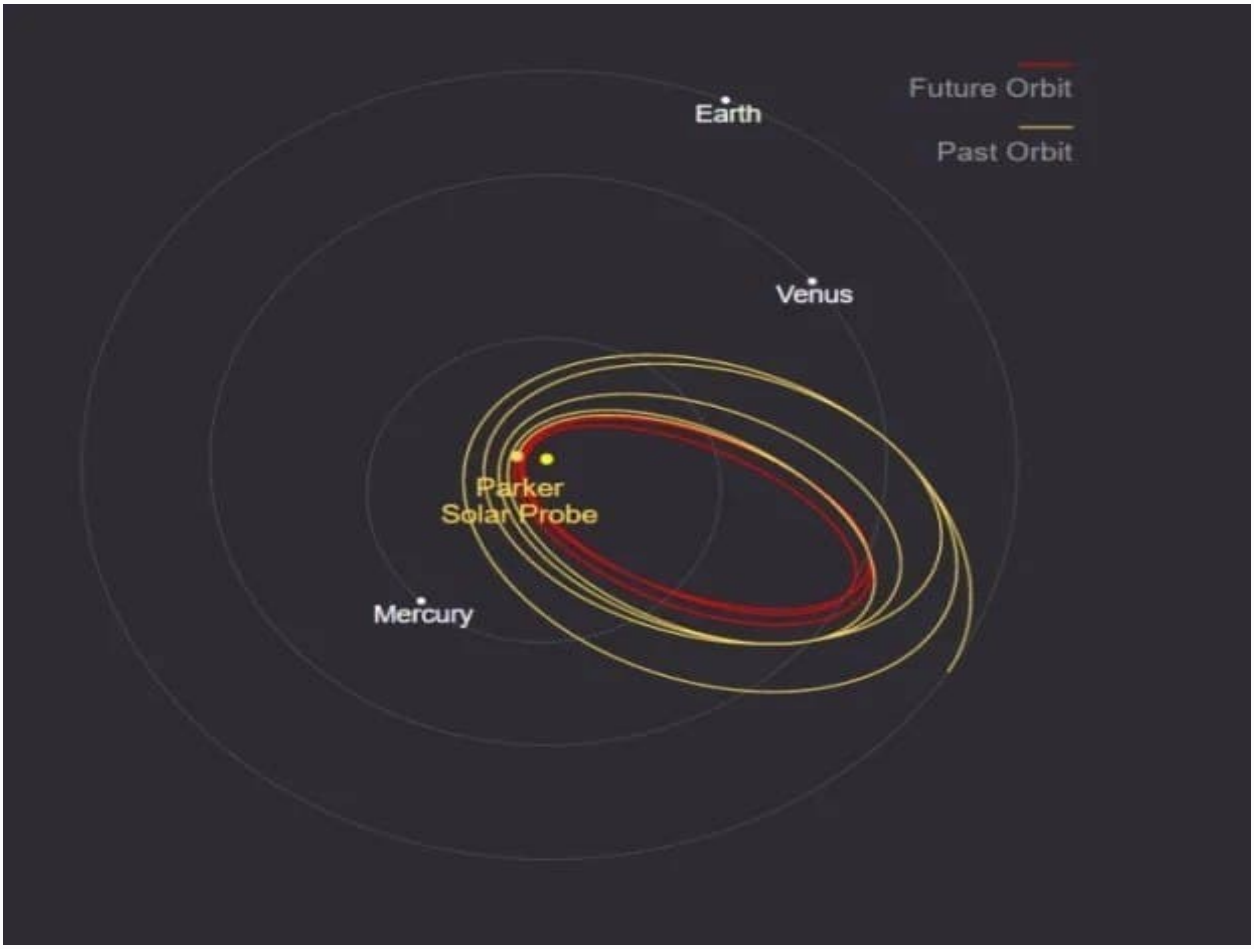

About the mission:

- NASA's historic Parker Solar Probe mission will revolutionize our understanding of the sun, where changing conditions can propagate out into the solar system, affecting Earth and other worlds.
- Parker Solar Probe will travel through the sun's atmosphere, closer to the surface than any spacecraft before it, facing brutal heat and radiation conditions — and ultimately providing humanity with the closest-ever observations of a star.

Journey:

- In order to unlock the mysteries of the sun's atmosphere, Parker Solar Probe will use Venus' gravity during seven flybys over nearly seven years to gradually bring its orbit closer to the sun.

- The spacecraft will fly through the sun's atmosphere as close as 3.9 million miles to our star's surface, well within the orbit of Mercury and more than seven times closer than any spacecraft has come before.

Parker Solar Probe has three detailed science objectives:

1. Trace the flow of energy that heats and accelerates the solar corona and solar wind.
2. Determine the structure and dynamics of the plasma and magnetic fields at the sources of the solar wind.
3. Explore mechanisms that accelerate and transport energetic particles.

पार्कर सोलर प्रोब

नासा की जांच ने हाल ही में सूर्य के साथ बेहद करीबी मुठभेड़ की। जांच हमारे तारे की सतह से सिर्फ 5.3 मिलियन मील दूर थी और 363,660 मील प्रति घंटे की हास्यास्पद गति से गुजरी, जिससे यह अब तक की सबसे तेज कृत्रिम वस्तु बन गई।

• इसके अतिरिक्त, पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के निकट के पास से बचने के लिए निकटतम उपग्रह के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।

आगे क्या?

जांच कक्षा में जारी रहेगी और तेजी से सूर्य के करीब पहुंच जाएगी, अंततः सतह से 4.3 मिलियन मील के भीतर 430,000 मील प्रति घंटे से ऊपर की गति से आ रही है। प्रत्येक पास के साथ, जांच हमारे तारे के बारे में मूल्यवान डेटा एकत्र करती है और वैज्ञानिकों को व्याख्या करने के लिए

जानकारी को वापस पृथ्वी पर भेजती है। सौर हवा के बारे में जानकारी, और क्षेत्र में धूल के कणों की मात्रा जांच द्वारा एकत्र किए जाने वाले डेटा के दो मुख्य सेट हैं

मिशन के बारे में:

• नासा का ऐतिहासिक पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, जहां बदलती स्थितियां पृथ्वी और अन्य दुनिया को प्रभावित करते हुए सौर मंडल में फैल सकती हैं।

• पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वायुमंडल से होकर गुजरेगा, इससे पहले किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में सतह के करीब, क्रूर गर्मी और विकिरण की स्थिति का सामना करना पड़ेगा – और अंततः मानवता को एक तारे के निकटतम अवलोकन के साथ प्रदान करेगा।

सफ़र:

• सूर्य के वातावरण के रहस्यों को उजागर करने के लिए, पार्कर सोलर प्रोब लगभग सात वर्षों में सात फ्लाईबाई के दौरान शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके धीरे-धीरे अपनी कक्षा को सूर्य के करीब लाएगा।

• अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल से होते हुए हमारे तारे की सतह के 3.9 मिलियन मील के करीब, बुध की कक्षा के भीतर और किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में सात गुना अधिक करीब से उड़ान भरेगा।

पार्कर सोलर प्रोब के तीन विस्तृत विज्ञान उद्देश्य हैं:
1. सौर कोरोना और सौर पवन को गर्म करने और तेज करने वाली ऊर्जा के प्रवाह का पता लगाएं।
2. सौर हवा के स्रोतों पर प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों की संरचना और गतिशीलता का निर्धारण करें।
3. उन तंत्रों का अन्वेषण करें जो ऊर्जावान कणों को गति और परिवहन करते हैं।

Sweden elects 1st Female Prime Minister Magdalena Andersson

The former Finance Minister of Sweden, **Eva Magdalena Andersson** from the Social Democratic Party (SDP) won her **2nd election** and became the **1st female Prime Minister (PM) of Sweden.** On 24 November 2021, she was first elected as the PM but later resigned after her coalition partner (Green Party) quit the government and the budget failed to pass. Swedan's Parliament is known as **Riksdag.** Sweden is the last Nordic country to get a female Prime Minister.

About the Magdalena Andersson:

- Magdalena Andersson was born on 23 January 1967. She is a 54-year-old Swedish politician and economist serving as the PM from the Social Democratic Party or SDP.
- She began her political career as a political adviser to then PM Goran Persson in 1996 and then as Director of Planning.
- In 2004 she began to work in the Ministry of Finance as State Secretary.
- She became the head of the SDP on November 4, 2021. She is the second woman leader of the SDP.

- Sweden Capital: Stockholm;
- Sweden Currency: Swedish krona

स्वीडन ने पहली महिला प्रधान मंत्री मैग्डेलेना एंडरसन चुनी
स्वीडन की पूर्व वित्त मंत्री, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपी) की ईवा मैग्डेलेना एंडरसन ने अपना दूसरा चुनाव जीता और स्वीडन की पहली महिला प्रधान मंत्री (पीएम) बनीं। 24 नवंबर 2021 को, उन्हें पहले पीएम के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में उनके गठबंधन सहयोगी (ग्रीन पार्टी) द्वारा सरकार छोड़ने और बजट पारित होने में विफल रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। स्वीडन की संसद को रिक्सडैग के नाम से जाना जाता है। महिला प्रधान मंत्री पाने वाला स्वीडन अंतिम नॉर्डिक देश है।

मैग्डेलेना एंडरसन के बारे में:

• मैग्डेलेना एंडरसन का जन्म 23 जनवरी 1967 को हुआ था। वह 54 वर्षीय स्वीडिश राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री हैं, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या एसडीपी के प्रधान मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

• उन्होंने 1996 में तत्कालीन पीएम गोरान पर्सन के राजनीतिक सलाहकार और फिर योजना निदेशक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की।
• 2004 में उन्होंने वित्त मंत्रालय में राज्य सचिव के रूप में काम करना शुरू किया।
• वह 4 नवंबर, 2021 को एसडीपी की मुखिया बनीं। वह एसडीपी की दूसरी महिला नेता हैं।
• स्वीडन राजधानी: स्टॉकहोम;
• स्वीडन मुद्रा: स्वीडिश क्रोना

V Praveen Rao wins 7th Dr. M.S. Swaminathan Award for 2017-19

Vice-Chancellor (VC) of Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University, **V Praveen Rao** wins the **7th Dr M S Swaminathan Award** for the period **2017-19.** It is a biennial national (every 2 years) award that was presented by the retired ICAR (Indian Council of Agricultural Research) Employees Association (RICAREA) and Nuziveedu Seeds Limited. It carries a cash prize of **INR 2 lakh** and a citation.

Highlights of the award:

The Selection Committee, headed by former ICAR Director-General, RS Paroda has decided to select V Praveen Rao for the award recognising his contributions in the fields of 'agricultural research, teaching, extension and administration'. Praveen Rao handled 13 research and 6 consultancy projects on micro-irrigation in India, Israel and South Africa.

About Dr M S Swaminathan Award :

- This prestigious award was instituted in **2004** in honour of **Dr M.S. Swaminathan** the main architect of **India's Green Revolution.**
- This award is a lifetime achievement award for outstanding contributions to agricultural research and development and for overall food security and sustainability of agriculture.
- The award is open to all, irrespective of his/her nationality.

वी प्रवीण राव ने जीता 7वां डॉ. एम.एस. 2017-19 के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार

प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी), वी प्रवीण राव ने 2017-19 की अवधि के लिए 7 वां डॉ एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जीता। यह एक द्विवार्षिक राष्ट्रीय (प्रत्येक 2 वर्ष) पुरस्कार है जो सेवानिवृत्त ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) कर्मचारी संघ (RICAREA) और नुज़िवेडु सीड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें INR 2 लाख का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

पुरस्कार की मुख्य विशेषताएं:

पूर्व आईसीएआर महानिदेशक, आरएस परोदा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने वी प्रवीण राव को 'कृषि अनुसंधान, शिक्षण, विस्तार और प्रशासन' के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए पुरस्कार के लिए चयन करने का निर्णय लिया है। प्रवीण राव ने भारत, इज़राइल और दक्षिण अफ्रीका में सूक्ष्म सिंचाई पर 13 अनुसंधान और 6 परामर्श परियोजनाओं को संभाला।

डॉ एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में:

• यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2004 में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार थे।

• यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए और समग्र खाद्य सुरक्षा और कृषि की स्थिरता के लिए एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है।

• पुरस्कार सभी के लिए खुला है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो।

Smart Cities Mission (SCM)

The deadline for completing projects under the Smart Cities Mission (SCM) has been extended for all 100 participating cities to June 2023 due to the delays caused by COVID-19 and based on a NITI Aayog recommendation in August.

Smart Cities mission:

- GoI launched the smart cities mission in 2015.
- The cities were given five years to complete the projects under the mission, with the first set of Smart Cities expected to complete in 2021.
- The objective is to integrate city functions, utilize scarce resources more efficiently, and improve the quality of life of citizens.
- It is an innovative initiative under **the Ministry of Housing and Urban Affairs.**
- It is **a Centrally Sponsored Scheme.**

Smart city is envisaged to have four pillars:

1. Social Infrastructure.
2. Physical Infrastructure.
3. Institutional Infrastructure (including Governance).
4. Economic Infrastructure.

Progress made under this scheme (as of June 2021):

- Of the total proposed projects under this mission, 5,924 projects have been tendered, work orders have been issued for 5,236 and 2,665 projects are fully operational.
- 212 PPP projects worth Rs. 24,964 crore have been grounded/completed
- 70 Smart cities have developed. operationalized their Integrated Command and Control Centres (ICCCs) in the country.

Challenges ahead:

1. A lot of progress is desired in creating energy-efficient and green buildings.
2. Making Urban Bodies self-reliant.
3. The share of public transport is declining, it needs to be increased to meet the needs of increasing urbanization.
4. Rising air pollution, increase in road congestion due to an increase in urbanization.

स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)

स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) के तहत परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा सभी 100 भाग लेने वाले शहरों के लिए जून 2023 तक बढ़ा दी गई है, जो कि COVID-19 के कारण हुई देरी और अगस्त में NITI Aayog की सिफारिश के आधार पर है।

स्मार्ट सिटी मिशन:

• भारत सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया था।

• मिशन के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शहरों को पांच साल का समय दिया गया था, जिसमें स्मार्ट सिटी का पहला सेट 2021 में पूरा होने की उम्मीद है।

• इसका उद्देश्य शहर के कार्यों को एकीकृत करना, दुर्लभ संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
• यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक अभिनव पहल है।
• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

स्मार्ट सिटी में चार स्तंभ होने की परिकल्पना की गई है:
1. सामाजिक अवसंरचना।
2. भौतिक अवसंरचना।
3. संस्थागत अवसंरचना (शासन सहित)।
4. आर्थिक अवसंरचना।

इस योजना के तहत की गई प्रगति (जून 2021 तक):
• इस मिशन के तहत कुल प्रस्तावित परियोजनाओं में से, 5,924 परियोजनाओं की निविदा दी गई है, 5,236 के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं और 2,665 परियोजनाएं पूरी तरह से चालू हैं।
• 212 पीपीपी परियोजनाएं रु. 24,964 करोड़ को आधार बनाया/पूरा कर दिया गया है

• 70 स्मार्ट शहर विकसित हुए हैं। देश में अपने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) का संचालन किया।

आगे की चुनौतियां:

1. ऊर्जा दक्ष और हरित भवनों के निर्माण में काफी प्रगति अपेक्षित है।
2. शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाना।
3. सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी घट रही है, बढ़ते शहरीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की जरूरत है।
4. बढ़ता वायु प्रदूषण, शहरीकरण में वृद्धि के कारण सड़कों की भीड़भाड़ में वृद्धि।

India, Bangladesh to celebrate Maitiri Diwas on 6 December

India and Bangladesh have decided to celebrate **December 6,** the day on which India formally recognized Bangladesh, as **"Maitri Diwas" (Friendship Day).** During the visit of PM Narendra Modi to Bangladesh in March 2021 to attend the national day of Bangladesh, it was decided to commemorate 6 December as Maitri Diwas (Friendship Day). Ten days before the liberation of Bangladesh, India had recognised Bangladesh on **6 December 1971.** India was one of the first countries to establish bilateral diplomatic ties with Bangladesh.

According to the joint statement issued by the Ministry of External Affairs, Prime Minister Modi highlighted that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, one of the

greatest leaders of modern times, will be remembered for his courage and indelible contribution to Bangladesh's emergence as a sovereign country.

About the Maitri Diwas:

- The Maitri Diwas is being commemorated in 18 countries around the world apart from Dhaka and Delhi. These countries are Belgium, Canada, Egypt, Indonesia, Russia, Qatar, Singapore, UK, Australia, France, Japan, Malaysia, Saudi Arabia, South Africa, Switzerland, Thailand, UAE and USA.
- The holding of Maitri Diwas is a reflection of the deep and abiding friendship between the people of India and Bangladesh that have been forged in blood and shared sacrifices.

भारत, बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैतीरी दिवस मनाएंगे

भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मनाने का फैसला किया है, जिस दिन भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को "मैत्री दिवस" (मैत्री दिवस) के रूप में मान्यता दी थी। मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस (मैत्री दिवस) के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। बांग्लादेश की मुक्ति से दस दिन पहले, भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी थी। भारत बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार, प्रधान मंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आधुनिक समय के महानतम नेताओं में से एक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान

को उनके साहस और बांग्लादेश के एक संप्रभु देश के रूप में उभरने में अमिट योगदान के लिए याद किया जाएगा।

मैत्री दिवस के बारे में:

• ढाका और दिल्ली के अलावा दुनिया भर के 18 देशों में मैत्री दिवस मनाया जा रहा है। ये देश हैं बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, कतर, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूएई और यूएसए।

• मैत्री दिवस का आयोजन भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और स्थायी मित्रता का प्रतिबिंब है जो रक्त और साझा बलिदान में जाली है।

Himachal Pradesh Police honoured with 'President's Colour' award

Himachal Pradesh Police has conducted the **'President's Colour Award' ceremony** at Shimla's historic Ridge Ground. The Governor bestowed the 'President's Color Award' to the State Police on this occasion. Director-General of Police **Sanjay Kundu** received the award on the behalf of state police. The Chief Guest was Governor **Rajendra Vishwanath Arlekar,** while Chief Minister Jai Ram Thakur was also there as a special guest. Himachal Pradesh Police is India's eighth state police force to receive this honour.

About the President Colour:

‘President Colour’ is a special achievement, demonstrating that the state police ranks highly in the service of humanity, as well as performance, professionalism, integrity, human rights protection, and other factors.

हिमाचल प्रदेश पुलिस को 'प्रेसीडेंट्स कलर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज ग्राउंड में 'राष्ट्रपति रंग पुरस्कार' समारोह आयोजित किया है। राज्यपाल ने इस अवसर पर राज्य पुलिस को 'राष्ट्रपति रंग पुरस्कार' प्रदान किया। राज्य पुलिस की ओर से पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुरस्कार ग्रहण किया। मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे, जबकि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस यह सम्मान पाने वाली भारत की आठवीं राज्य पुलिस बल है।

राष्ट्रपति रंग के बारे में:

'प्रेसिडेंट कलर' एक विशेष उपलब्धि है, जो दर्शाती है कि राज्य पुलिस मानवता की सेवा के साथ-साथ प्रदर्शन, व्यावसायिकता, अखंडता, मानवाधिकार संरक्षण और अन्य कारकों में उच्च रैंक रखती है।

National Green Tribunal (NGT)

The **National Green Tribunal (NGT),** Eastern Zone, has imposed a fine of ₹2 crore on the Jindal Steel and Power Limited (JSPL) for changing the natural course of **Kurbadahali Nalla** (water channel) in Odisha's Angul district.

What's the issue?

A complaint filed with NGT said that the JSPL had unauthorisedly usurped **the Nandira River** in Angul in connivance with the State authorities and filled it up with earth thereby completely obliterating the river.

About NGT:

- Established on **18th October, 2010** under **the National Green Tribunal Act 2010**.
- Established **for effective and expeditious disposal of cases** relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources.
- **New Delhi is the Principal Place of Sitting** of the Tribunal and Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai shall be the other four places of sitting of the Tribunal.
- The Tribunal is **not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure, 1908,** but **shall be guided by principles of natural justice.**
- NGT is **mandated to make disposal of applications or appeals finally within 6 months of filing of the same.**

With the establishment of the NGT, **India became the third country in the world to set up a specialised environmental tribunal,** only **after Australia and New Zealand,** and **the first developing country to do so.**

Composition:

Sanctioned strength: The act allows for up to 40 members (20 expert members and 20 judicial members).

Chairman: Is the administrative head of the tribunal, also **serves as a judicial member and is required to be a serving or retired Chief Justice of a High Court or a judge of the Supreme Court of India.**

Selection:

1. **Members** are chosen by a selection committee (headed by a sitting judge of the Supreme Court of India) that reviews their applications and conducts interviews.
2. **The Judicial members** are chosen from applicants who are serving or retired judges of High Courts.
3. **Expert members** are chosen from applicants who are either serving or retired bureaucrats not below the rank of an Additional Secretary to the Government of India (not below the rank of Principal Secretary if serving under a state government) with a minimum administrative experience of five years in dealing with environmental matters. Or, the expert members must have a doctorate in a related field.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), पूर्वी क्षेत्र ने ओडिशा के अंगुल जिले में कुर्बदहली नाला (जल चैनल) के प्राकृतिक पाठ्यक्रम को बदलने के लिए जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

मुद्दा क्या है?

एनजीटी में दर्ज एक शिकायत में कहा गया है कि जेएसपीएल ने राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत से अंगुल में नंदीरा नदी को अनाधिकृत रूप से हड़प लिया और इसे मिट्टी से भर दिया जिससे नदी पूरी तरह से खत्म हो गई।

एनजीटी के बारे में:

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर, 2010 को स्थापित किया गया।

• पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए स्थापित।

• नई दिल्ली ट्रिब्यूनल के बैठने का प्रमुख स्थान है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई ट्रिब्यूनल के अन्य चार स्थान होंगे।

• ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
• एनजीटी को आवेदनों या अपीलों को दाखिल करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान करना अनिवार्य है।
एनजीटी की स्थापना के साथ, भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया और ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया।

संयोजन:
स्वीकृत शक्ति: अधिनियम 40 सदस्यों (20 विशेषज्ञ सदस्य और 20 न्यायिक सदस्य) तक की अनुमति देता है।
अध्यक्ष: ट्रिब्यूनल का प्रशासनिक प्रमुख है, न्यायिक सदस्य के रूप में भी कार्य करता है और उसे उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है।
चयन:
1. सदस्यों का चयन एक चयन समिति (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में) द्वारा

किया जाता है जो उनके आवेदनों की समीक्षा करती है और साक्षात्कार आयोजित करती है।

2. न्यायिक सदस्य उन आवेदकों में से चुने जाते हैं जो उच्च न्यायालयों के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।

3. विशेषज्ञ सदस्यों को उन आवेदकों में से चुना जाता है जो या तो सेवारत या सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं जो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हैं (यदि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं तो प्रधान सचिव के पद से नीचे नहीं) न्यूनतम पांच प्रशासनिक अनुभव के साथ पर्यावरणीय मामलों से निपटने में वर्ष। या, विशेषज्ञ सदस्यों के पास संबंधित क्षेत्र में डॉक्टरेट होना चाहिए।